बहुत महत्व है । क्या मंत्री महोदय उस की महत्ता को दृष्टि में रखते हुए यह समझते हैं कि उस का कनवर्शन होना चाहिए ?

प्रो० मधु दण्डवते : जनता सरकार मार्च में बनी थी । कई ऐसी कनवर्शन की स्कीम्ज थीं जो मेरे रेलवे मंत्री बनने से पहले शुरू हुई थी जो पैंडिंग वर्क्स मैंनें शुरू किये हैं उन्हे हम लोगों ने पैंडिंग रखा है ऐसा नहीं है वे पुरानी सरकार के पैंडिंग वर्क्स हैं उन्हें पुरानी सरकार ने शुरू किया था इस लिए हम उन्हें पूरा न करें ऐसी नकारात्मक भूमिका हमारी नहीं है और इसलिए हम ने उन्हें पूरा करना है ।

Annual production by Multinational Drug Companies

*493. SHRI NATWARLAL B. PARMAR: Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) the percentage of the annual production of formulations and bulk drugs being controlled by the multinational companies in our country;

(b) whether Government have any idea to set up new drug industries only in the public sector; and

(c) if so, the steps being taken in this regard?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) The total value of production of Bulk Drugs & formulations in the country during 1976-77 is estimated at Rs. 150 crores and Rs. 700 crores respectively. The value of production by the foreign firms is estimated to be Rs. 63 crores & Rs. 292 crores respectively representing 42 per cent and 41.7 per cent of the total.

(b) and (c). No, Sir. While a leadership role is assigned to the public sector, proposals received from other sectors of drug industry will also be considered on merits, keeping in mind the areas demarcated for the public sector and the Indian sector and the rest which is open to all Sectors.

SHRI NATWARLAL B. PARMAR: I want to know whether it has come to the notice of the Government that foreign companies are importing intermediates and bulk drug from their principals at high prices to push up their sales turnover of formulations.

What are the details in this regard and extra profits made through such imports?

SHRI H. N. BAHUGUNA: This is a very wide question. But, it is a fact that, in some cases, some facts have come to the notice of the Government even to the outgoing Government; the Hathi Committee had gone into that part of the question. And the Government is likely to take a decision soon in all such matters so as to remove such types of malpractices involving import of basic or intermediate drugs from the principals by these companies at exorbitant rates.

श्री कल्याण जैन : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो दवाई बनाने वाली कम्पनियां हैं वे अपना नाम बेचती हैं बजाय दवा बेचने के एक एस्प्रो हैं जिसे एस्प्रो कम्पनी 10 पैसे में बेचती है और वही पेटेन्ट एक पैसे में दूसरी कम्पनी बेचती है तो क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जो हाथी कमेटी ने सिफारिश की है कि कम्पनी नहीं बिके दवा बिके उस के ऊपर सरकार क्या कर रही है ? इस के द्वारा करोड़ों और अरबों रुपया मल्टी नेशनल कम्पनियां बना रही हैं । हाथी कमेटी ने सिफारिश की हैं कि जैनरिक नेम दवाइयों का होना चाहिए और उस पर सिफ कम्पनी ब्रान्ड होना चाहिए उस के बारे में सरकार क्या कर रही है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : हाथी कमेटी ने पूरे तौर पर ऐसी सिफारिश तो नहीं की है कि हर दवा का जैनरिक नेम चले लेकिन उन्हों ने कहा था कि कुछ दवाइयों के जैनरिक नेम शुरू करने चाहिएं । इस प्रश्न पर हाथी कमेटी के अनेक प्रश्नों के साथ

साथ फैसला आएगा । आज निर्णय करना और कहना मुश्किल है कि इस में गवर्नमेंट का क्या रुख होगा । आज जो माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है और हाथी कमेटी ने जो कहा है वह अत्यन्त विचारणीय विषय है और उन पर विचार होगा ।

SHRI VAYALAR RAVI: Sir, Indeed every other matter is with the drug industry. The Hathi Committee is now a talking point. It is true that Hathi Committee has gone into more details in the working of the Indian Multi-national Companies in drugs in this country and has made various suggestions.

In this background, all the time the Minister and the former Government as also the present Government went on discussing and considering the matter. I want to know how long will the hon. Minister take to come to a final decision? And will he come before Parliament with a national policy on the drug manufacturing as well as on pricing?

SHRI H. N. BAHUGUNA: The decision on the Hathi Committee Report shall have to be brought before Parliament. But, if the Parliament is not in session and decision is taken, then that decision will have to be announced. But I quite agree with my hon. friend, Shri Ravi, that too much time has been taken by the previous Government. We do not want to take even half the time which the then Government has taken in deciding this matter. But, as I said earlier, I can assure Mr. Ravi that we have not lost a single day in coming to a decision in regard to the perspectives in the field of operations of various sectors of drug industries—nationals, multi-national, large and small-scale, sectors as also the pricing pattern of all basic, bulk drugs and formulations and various questions regarding generic *versus* brank names.

डा० बलदेव प्रकाश : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है और बेसिक ड्रग्स हैं उन की कीमत चूंकि बहुत बढ़ गई है तो सरकार को जो पब्लिक सैक्टर की कम्पनियां हैं उन में उन की कीमत कम कर के गरीब आदमियों को वह दवाएं सुलभ करने की पालिसी पर वह विचार करेंगे और उन पर जो एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स वगैरह लगने के कारण कीमत दस पन्द्रह परसेंट और बढ़ रही है उस को कम कर के देश के अन्दर सस्ती दवाइयां देने का प्रबन्ध करेंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : दवाइयों के दाम के सम्बन्ध में भी कैसे उन के मूल्य रखे जायें या कैसे वह मूल्य निर्धारित हों यह प्रश्न भी इस वक्त सरकार के सामने विचारणीय है और उस के दूसरे पहलू हैं कि उस पर एक्साइज क्या हो आक्ट्राय क्या हो सेल्स टैक्स क्या हो। अनेक चीजें उस में हैं जिस में अकेले इस सरकार का ही नहीं, प्रदेशीय सरकारों का भी हाथ है तो जिस समय दवाओं के मूल्य के सम्बन्ध में हम निर्णय करेंगे। उस समय इन सब प्रश्नों पर भी विचार किया जाएगा ।

डा० बलदेव प्रकाश : निर्णय कब तक हो जाएगा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा : आशा है इसी वर्ष में होना चाहिए ।

PROF. DILIP CHAKRAVARTY: Will the Minister be pleased to give an assurance in this House about the time-bound implementation of the recommendations of the Hathi Committee? One of the important recommendations of the Hathi Committee is to initiate public sector in the drug industry. I would like to know when the public sector is initiated in the drug industry, the workers' participation in that will be strengthened.

SHRI H. N. BAHUGUNA: I would merely say that the public sector is already in a dominant position in

drug industry. we are committed to further strengthen the public sector participation in drug industry. Sir, the Hathi Committee has made 262 recommendations and we have gone into them. It is our effort to see if we can decide as early as possible. Perhaps, it may be possible to do so in this very year. Sir, so far as the question regarding workers' participation is concerned it is something beyond the scope of the Hathi Committee, I for one would say although workers' participation in the management may be a laudable thing yet we have to look at it from many angles. We have to know as to how the workers' themselves look at this matter. It is a complicated matter and I cannot, at this instance, announce any policy.

Proposal for setting up oil refinery in Gujarat

*494. SHRI AHMAD M. PATEL: Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to set up oil refinery in Gujarat State during the next Plan period;

(b) if so, the location selected; and

(c) the broad outlines thereof?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) There is no proposal presently under consideration of Government for setting up another Oil Refinery specifically in Gujarat State during the next Plan period.

(b) and (c). Do not arise.

श्री अहमद एम० पटेल : क्या स्टेट गवर्नमेंट ने आयल रिफाइनरी के सेंट-अप के लिए कोई पर्टिकुलर लोकेशन की प्रोपोजल भजी है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं कह सकता हूं कि गुजरात की सरकार बड़ी सतर्क सरकार है । आयल रिफाइनरी के संबंध में ही नहीं बल्कि पैट्रोलियम पर आधारित जितने भी उद्योग हैं उन सब के सम्बन्ध में बराबर परामर्श कर रह है । रिफाइनरी खास के संबंध में कोयली के एक्सपेंशन के बारे में लिखा है सात मिलियनको उस की कैपेसिटी हो सके इस तरह से एक्सपेंशन प्रोग्राम चल रहा है । गवर्नमेंट ने एक कमेटी बना दी है कि भविष्य में कहां पर रिफाइनिंग कैपेसिटी लगाई जाये और गुजरात सरकार को भी बता दिया गया है ।

श्री अहमद एम० पटेल : क्या मंत्री जी कोई दूसरी आइल रिफाइनरी के लिए सोच रहे हैं या जो अभी चल रही है वही काफी है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : गुजरात में जो तेल मिलता है भूमि में उस के लिए कोयली काफी है । यही नहीं कोयली के लिए हम बाम्बे हाई से भी तेल लेने वाले हैं । 70 लाख टन तेल रेफाइन करना कोई साधारण रेफाईनरी नहीं हैं बल्कि यह देश की सबसे बड़ी रिफानरी बन जायेगी । इसलिए यह प्रश्न नहीं है कि तेल कितना है बाम्बे हाई का तेल रेफाइन करने के लिए गुजरात की जो लोकेशन है वह आइडियल है और इस दृष्टि से अगर जरूरत पड़ेगी तो उस पर भी विचार करेंगे ।

SHRI VINODBHAI B. SHETH: In view of the availability of oil at Bombay High and drilling operations in Kandla and expanding petro-chemicals complex near Surat and Baroda and industrial peace in Gujarat and also the proximity of Persian Gulf will the Hon'ble Minister assure a refinery—out of necessity and on merit—for Gujarat to be set-up in the next Plan?

SHRI H. N. BAHUGUNA: All that the hon. Member has suggested is in national interest and therefore if and when the question of location of a refinery comes up all these factors will be borne in mind by the Committee. Right now we have no such proposal.